CMYK

Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

◘ वर्ष- 28 ◘ अंक- 61 ◘ रायपुर, गुरुवार 27 मार्च 2025 ◘ पृष्ठ-8 ◘ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • बिलासपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

सब जानते हैं छत्तीसगढ़ के युवाओं को सट्टे की लत किसने लगाया

चाहे कोई भी दोषी हो बख्शा नहीं जाएगा : साय

रायपुर, 27 मार्च (हाईवे चैनल)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बेंगलुरु में आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्ट कार्यक्रम से आज रायपुर लौटे. रायपुर एयरपोर्ट पर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए महादेव सट्टा एप मामले में सीबीआई रेड और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार किया. सीएम साय ने कहा कि भूपेश बघेल के पास दूसरा बोलने के लिए कोई रास्ता नहीं है. सीबीआई के द्वारा महादेव सट्टा एप पर यह जांच हो रही है. सबको मालूम है किस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को सट्टे की लत लगा दी गई थी. अब मामले में जांच सीबीआई कर रही है.

इसके साथ ही सीएम साय ने भूपेश बघेल के बयान को लेकर कहा कि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो कुछ भी बोलते हैं. इसमें चाहे कोई भी हो दोषीदार बख्शे नहीं जाएंगे. इसमें भाजपा और कांग्रेस के करीबी होने का कोई सवाल नहीं है. जो भी लिंक पूरे प्रकरण से जुड़ा होगा, उन सभी के ऊपर कार्रवाई होगी. बैंगलुरु इन्वेस्टर्स मीट कार्यक्रम को लेकर सीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि इन्वेस्टर्स कनेक्ट का कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हुआ. छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति की निवेशकों को जानकारी दी गई. इससे उद्यमी और निवेशक काफी आकर्षित हुए हैं. कल 3700 करोड़ रुपये का निवेश का प्रस्ताव सौंपा गया है. कुछ कंपनियों से एमओयू हुआ है. इंजीनियरिंग और आईटी के क्षेत्र में यहां पर उद्योग लगेंगे. इस तरह से बहुत अच्छा हमारा यह इन्वेस्टर्स कनेक्ट का कार्यक्रम रहा है. इसके पहले भी हमने दिल्ली और मुंबई में इस तरह का कार्यक्रम किया था, जिसमें काफी अच्छा रुझान आया है. उद्योगपति बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं. सीएम साय ने बताया कि नई उद्योग नीति लॉन्च करने के बाद करीब 4 लाख 40 हजार करोड़ के प्रस्ताव मिले हैं. यह हमारी नई उद्योग नीति का ही असर है. 3700 करोड़ के जो निवेश के प्रस्ताव दिए हैं,

सीबीआई की एएसपी अभिषेक माहेश्वरी के घर फिर से दस्तक, जांच के लिए दो गाड़ियों में पहुंची टीम

राजनांदगांव, 27 मार्च (हाईवे चैनल)। महादेव सट्टा एप मामले में सीबीआई की कार्रवाई जारी है. बुधवार की कार्रवाई के बाद आज एक बार फिर सीबीआई की टीम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक माहेश्वरी के कंचनबाग के सनसिटी स्थित घर पहुंची. सीबीआई की टीम ने बुधवार को कार्रवाई के बाद घर को सील कर दिया था. आज फिर से दो गाड़ियों में अभिषेक माहेश्वरी के घर पहुंची सीबीआई की टीम ने सील को खोलकर दोबारा से अपनी जांच शुरू की.

हमने ही कार्रवाई की तो हम पर संरक्षण का आरोप कैसेः भूपेश बघेल

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सीबीआई छापेमारी पर बड़ा सवाल

इधर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महादेव सट्टा एप को लेकर सीबीआई की छापेमारी को लेकर सवाल खड़ा किया है. सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर किए अपने पोस्ट में उन्होंने कहा कि जब हमने ही कार्रवाई की तो हम पर संरक्षण का आरोप कैसे? ये कैसी जाँच है? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा है कि महादेव एप के बारे में देश में कोई नहीं जानता था. मुख्यमंत्री रहते कांग्रेस सरकार में ही 74 स्न्नढ्ढक्र दर्ज हुई हैं. 200 से अधिक गिरफ्तारी हुई हैं. 2000 से अधिक बैंक खाते सीज किए गए. हमारी सरकार में ही गूगल को पत्र लिखकर प्ले स्टोर से इस एप को हटाया गया. वहीं ईडी पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी ने झूठी खबर छपवाई कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल दुबई में गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन वे वहाँ शिवकथा की जजमानी करते पाए गए. तो ये कैसी जाँच है? इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेशबघेल ने पोस्ट में कहा कि सीबीआई अधिकारियों ने न तो मेरे रायपुर स्थित शासकीय आवास में सूचना दी, और न ही भिलाई निवास में कोई सूचना दी. मेरी अनुपस्थिति में मेरे शासकीय आवास में बिना मुझे सूचना दिए प्रवेश करना पूर्णतः अनाधिकृत है. क्या भाजपा अब सीबीआई के माध्यम से कोई षड्यंत्र रच रही है?

आरटीई में गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के मामले में सुनवाई, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट नीति बनाने के दिए निर्देश

बिलासपुर, 27 मार्च (हाईवे चैनल)। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के बच्चों को शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत निःशुल्क शिक्षा देने के मामले में पेश जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की युगलपीठ ने राज्य सरकार को इस मामले पर आदेश से छह महीने के भीतर एक स्पष्ट नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिया है।

दरअसल सीवी भगवंत राव ने अधिवक्ता देवर्षि ठाकुर के माध्यम से एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें 6 से 14 वर्ष के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में भी निःशुल्क शिक्षा देने की मांग की गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि शिक्षा के अधिकार कानून (आरटीई) के तहत इन बच्चों को भी समान अवसर मिलना चाहिए और राज्य सरकार को इस पर स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। इस मामले को लेकर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में पिछली सुनवाई में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज जारी कर दिया गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार के पास इस विषय पर कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं है। इस प्रकार यह न्यायालय राज्य को निर्देश देना उचित समझता है कि वह 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग' के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के संबंध में नीति तैयार करे, ताकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21ए में निहित आरटीई अधिनियम की भावना और उद्देश्य को कानून के अनुसार यथाशीघ्र अधिमानतः आज से छह महीने की अवधि के भीतर प्राप्त किया जा सके।

1 अप्रैल 2025 से बदल जाएंगे लोन के नियम

नई दिल्ली, 27 मार्च (न्यूज चैनल)। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों (प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग) में ऋण देने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए दिशा-निर्देश 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। इन बदलावों का उद्देश्य छोटे उधारकर्ताओं को राहत देना और बैंकों को अधिक पारदर्शिता के साथ काम करने के लिए प्रेरित करना है। आइए जानते हैं नए नियमों के मुख्य बिंदु इस प्रकार है-

आरबीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि 50,000 रुपये तक के छोटे ऋण पर बैंक किसी भी प्रकार का सेवा शुल्क या निरीक्षण शुल्क नहीं लगा सकेंगे। इसका उद्देश्य छोटे उधारकर्ताओं को अनावश्यक वित्तीय बोझ से बचाना है। यह कदम छोटे व्यवसायियों, किसानों और कम आय वाले लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। आरबीआई ने प्राथमिकता वाले क्षेत्र के तहत होम लोन की सीमा बढ़ा दी है। नए नियमों के अनुसार 50 लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों में अब 50 लाख रुपये तक का होम लोन पीएसएल के तहत आएगा, जो पहले 35 लाख था। मकान की कीमत 63 लाख रुपये तक हो सकती है, जो पहले 45 लाख रुपये थी। 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले केंद्रों में अब 45 लाख रुपये तक का होम लोन मिलेगा।

ब्रेकिंग न्यूज

लखनऊ पुनर्वास गृह में 4 बच्चों की मौत, 20 से ज़्यादा बीमार, खाने में जहर का संदेह

नई दिल्ली, 27 मार्च (न्यूज चैनल)। लखनऊ के पैरा इलाके में स्थित एक सरकारी पुनर्वास केंद्र में कथित तौर पर विषाक्त भोजन करने से चार बच्चों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य बीमार हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इस केंद्र के करीब 20 बच्चे मंगलवार शाम अचानक बीमार पड़ गए जिन्हें लोक बंधु राज नारायण संयुक्त अस्पताल ले जाया गया।

लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी. ने बताया, ''इस आश्रय गृह की दो लड़कियों और दो लड़कों समेत कुल चार बच्चों की मौत हुई है। इनकी उम्र 12 से 17 वर्ष के बीच है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इनके विसरा संरक्षित रखे जाएंगे।'' अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राजीव कुमार दीक्षित ने बृहस्पतिवार को बताया, ''पुनर्वास केंद्र से करीब 20 बच्चे मंगलवार शाम इस अस्पताल में लाए गए। ये सभी बच्चे मानसिक रूप से कमजोर हैं। सभी प्रयासों के बावजूद दो बच्चों की मौत हो गई।'' डॉ. दीक्षित ने कहा कि गंभीर रूप से बीमार दो बच्चों को एक दूसरे सरकारी अस्पताल के लिए रेफर किया गया है और शेष 16 बच्चों की हालत में सुधार हो रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि विभिन्न अस्पतालों में भर्ती बच्चों के अलावा, शेष बच्चों के स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए एक मेडिकल टीम भी आश्रय गृह भेजी गई है। उन्होंने कहा, आश्रय गृह में करीब सात बच्चों को चिकित्सक की देखरेख में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम आश्रय गृह में बच्चों पर नजर रख रही है। इस घटना को लेकर लखनऊ के जिलाधिकारी ने एक कमेटी बनाई है और स्वास्थ्य विभाग तथा खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी पीड़ित बच्चों से पूछताछ के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पुनर्वास केंद्र से जांच के लिए खाद्य नमूने लिए गए हैं।

बिरादरी की बातें

चूहा- सुनती हो, भूपेश बघेल कह रहे हैं कि छापे में मेरे यहां से कुछ नहीं मिला।
चुहिया- हां जी, तो सीबीआई लेने थोड़े आए थे वो तो भूपेश को दिल्ली जाने से रोकने आए थे।

भोरमदेव महोत्सव में भीड़ का हंगामा हजारों कुर्सियां तोड़ डालीं

कवर्धा, 27 मार्च (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भोरमदेव महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी के बीच दर्शकों की भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया है। भजन गायक हंसराज रघुवंशी के गायन के दौरान भीड़ ने 2 हजार से अधिक कुर्सियां तोड़े। सामने आने के लिए बेकाबू भीड़ ने जमकर हंगामा किया। जिसके बाद कार्यक्रम को बंद कराने की नौबत आ गई।

दो दिवसीय महोत्सव का गुरुवार को समापन है। कार्यक्रम में दर्शक दीर्घा के लिए 8 हजार कुर्सियां लगाया गया था। वहीं हंगामे के बाद कलेक्टर मंच के कोने में मायूस बैठे दिखे। गायक हंसराज की प्रस्तुति के बाद कार्यक्रम को बंद करना पड़ा। वहीं भीड़ को संभालने में शासन प्रशासन के पसीने छूट गए।

सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सैलरी में 14,600 रुपये की बढ़ोतरी!

बेसिक सैलरी बढ़कर हो जाएगी 51,480 रुपये

नई दिल्ली, 27 मार्च (न्यूज चैनल)। 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद से सरकारी कर्मचारियों के मन में यही सवाल था कि आखिर उनकी सैलरी में कितना इजाफा होगा। अब, गोल्डमैन सैक्स की ताजा रिपोर्ट ने इस सवाल का जवाब देने का दावा किया है। रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 14,000 रुपये से लेकर 19,000 रुपये तक का इजाफा हो सकता है। इस बढ़ोतरी का फायदा 2026 या 2027 तक सरकारी कर्मचारियों को मिलने की उम्मीद है।

फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों की औसत सैलरी लगभग 1 लाख रुपये प्रति माह है। 8वें वेतन आयोग के बाद इस सैलरी में 14 से 19 प्रतिशत तक का इजाफा हो सकता है। गोल्डमैन सैक्स के अनुमान के अनुसार, अगर सरकार 1.75 लाख करोड़ का बजट निर्धारित करती है तो सैलरी में औसतन 14,600 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं, 2 लाख करोड़ का बजट होने पर यह बढ़ोतरी 16,700 रुपये तक हो सकती है, और 2.25 लाख करोड़ के आवंटन पर कर्मचारियों को 18,800 रुपये तक का फायदा हो सकता है।

इस योजना से लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। यह बदलाव सरकारी कर्मचारियों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी थी, लेकिन आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अभी तक तय नहीं किए गए हैं। माना जा रहा है कि आयोग की रिपोर्ट 2026 या 2027 में लागू हो सकती है। वेतन आयोग के तहत सैलरी में बढ़ोतरी के लिए फिटमेंट फैक्टर भी तय किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, और अब कर्मचारियों की मांग है कि इसे बढ़ाया जाए। अगर यह 2.57 पर कायम रहता है तो न्यूनतम सैलरी 18,000 से बढ़कर 46,260 रुपये हो जाएगी, जबकि पेंशन 9,000 से बढ़कर 23,130 रुपये हो सकती है। हालांकि, अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 होता है, तो न्यूनतम सैलरी 34,560 रुपये हो सकती है। इस बढ़ोतरी का इंतजार सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, और अगले कुछ सालों में इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है।

गंगरेल में पर्यटन को बढ़ावा देने नहीं हो रहे नए प्रयास

एक्वेरियम, जू, पुरातत्व संग्रहालय, व्यू प्वांईट जैसे कई नवाचार से पर्यटन को मिल पायेगा बूस्ट

धमतरी, 27 मार्च (हाईवे चैनल)। गंगरेल बांध की ख्याति दूर दूर तक फैली है धमतरी के अलावा पूरे प्रदेश भर में पर्यटक यहां घूमने आते है। लेकिन यहां उम्मीद के अनुरुप पर्यटन का विकास नहीं हो पाया। नतीजन पर्यटक आते तो है लेकिन उन्हें एंजाय व एंडवेचर्स के नाम पर ज्यादा कुछ नसीब नहीं हो पाता है।

गंगरेल बांध में जल भराव क्षमता 32.150 टीएमसी है। बांध विशाल महानदी पर बना हुआ है। बांध का प्राकृतिक दृश्य मनमोहक है। चारो ओर हरी भरी वादियों के बीच अथाह पानी दृश्य को और भी ज्यादा आकर्षक और मोहक बनाता है। गंगरेल बांध में समय के साथ पर्यटन को बूस्ट देने कई नवाचार करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। सालों पहले बोटिंग की सुविधा शुरु की गई है। इसके बाद से कुछ नया नहीं हो पाया है। वाटर एक्टिविटी में भी कमी आई है। अब ज्यादातर बोटिंग ही होता है। ऐसे में पर्यटको का

गंगरेल बांध में नहीं रह गया कोई आकर्षक एडवेंचर्स एक्टिविटी

मनोरंजन करने कई नये प्रयास जैसे एक्वेरियम, जू, संग्रहालय आदि खोला जा सकता है। गंगरेल में वैसे ही पर्यटक पहुंचते है ऐसे में इस दिशा में प्रयास होंगे तो पर्यटकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। आज धमतरी व आसपास के जिलो के दूरदराज के लोग जू में जंगली जानवरों को देखने भिलाई, नया रायपुर जाते है। वहीं एक्वेरियम में अनेक प्रकार के मछलियों को निहारने की सुविधा धमतरी में नहीं है। गंगरेल में इससे भी पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। गंगरेल में संग्राहालय का निर्माण भी एक अच्छा प्रयास साबित हो सकता है। व्यू प्वांईट भी गंगरेल में वॉच टावर बनाकर बनाया जा सकता है। जिससे बांध के खूबसूरत नजारे का और भी अच्छे तरीके से दीदार हो सकें। लोगों की माने तो नवाचार तो कई हो सकते है। लेकिन इसके लिये मजबूत नेतृत्व और इच्छाशक्ति की आवश्यकता है जो कि अब तक स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों में नजर ही नही आई है। लोगों के अनुसार गंगरेल बांध के पर्यटन का बड़ा कारण मां अंगारमोती भी है। भक्तो की भीड़ ही पर्यटन को बढ़ावा देती है।

मानव वन बदहाल

सालों पहले पर्यटकों के मनोरंजन और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मानव वन का निर्माण बांध के पास किया गया लेकिन सालों से मानव वन बदहाल है। यहां एंट्री फीस 20 रुपये लिया जाता है। जबकि यहां 20 रुपये वसूलने लायक को चीज नहीं रह गई है। मचानहट है जो बुकिंग पर एंट्री दी जाती है। वुडन कॉर्टेज है जो कि आम लोगों के जद से बाहर है क्योंकि किराया ज्यादा है।

कैंसर, हार्ट और डायबिटीज की दवाएं होंगी महंगी!

नई दिल्ली, 27 मार्च (न्यूज चैनल)। भारत में जल्द ही कैंसर, डायबिटीज, हार्ट संबंधी रोगों की दवाओं और एंटीबायोटिक्स की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। सरकारी नियंत्रण में आने वाली इन दवाओं की कीमतों में 1.7त्न तक की वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। यह असर अगले दो से तीन महीनों में दिखाई दे सकता है, क्योंकि मौजूदा समय में इन दवाओं का स्टॉक 90 दिनों का पहले से ही उपलब्ध है।

90 दिन का स्टॉक उपलब्ध

एक रिपोर्ट के अनुसार, ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स के महासचिव राजीव ने बताया कि कच्चे माल और अन्य खर्चों में निरंतर हो रही बढ़ोतरी के कारण यह फैसला लिया गया है। इससे फार्मा इंडस्ट्री को कुछ राहत मिल सकती है। रसायन और उर्वरक से संबंधित संसद की स्थायी समिति के अनुसार, फार्मा कंपनियों पर दवाओं की कीमतें बढ़ाने और नियामक नियमों का उल्लंघन करने के आरोप लग चुके हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की रिपोर्ट में कहा गया है कि फार्मा कंपनियों ने 307 मामलों में नियमों का उल्लंघन किया है। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 के तहत दवाओं की अधिकतम कीमत तय की जाती है, और सभी निर्माता और विक्रेता इन कीमतों के भीतर ही दवाएं बेचने के लिए बाध्य होते हैं। इस साल के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 36 जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी को हटा देने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर क्रोनिक रोगों से पीड़ित मरीजों को राहत देने के लिए यह कदम उठाया गया है।

CMYK